दैनिक ट्रिब्यून

विश्व बैंक प्रदेश को कार्बन न्यूट्रल राज्य बनाने में मदद करे

मध्य हिमालयन जलागम विकास परियोजना की बैठक में मुख्यमंत्री धूमल का आग्रह

ट्रिब्यून न्यूज सर्विस

शिमला, 14 नवंबर। विश्व बैंक हिमाचल प्रदेश को देश का कार्बन न्यूट्रल राज्य बनाने में सहायता करे। यह बात मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने शिमला में आयोजित उच्च स्तरीय हिमाचल प्रदेश मध्य हिमालयन जलागम विकास परियोजना के कार्यान्वयन सम्बंधी बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार हिमालयन पारिस्थितिकीय के सभी बाहरी व आंतरिक स्रोतों के संरक्षण की सभी संभावनाओं को तलाश रही है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में विश्व बैंक की पहल स्वागत योग्य है जिससे हिमाचल प्रदेश को भविष्य में कार्बन न्यूट्रल राज्य के रूप में उभरने में सहायता मिलेगी।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण के लिए अनेक प्रभावी कदम उठाए हैं जिसके तहत हरे वृक्षों के कटान व प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबन्ध, विशेष पौधरोपण अभियान, प्रदूषण न फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को लगाने की स्वीकृति प्रदान करना शामिल है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई है।

प्रो. धूमल ने कहा कि मिड हिमालयन जलागम विकास परियोजना से राज्य की पारिस्थितिकीय सन्तुलन को बनाए रखने में सहायता मिली है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के लागू हो जाने के बाद उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं तथा इससे ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के लागू होने से घरेलू आय में 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे पांच प्रतिशत परिवार ए.पी.एल श्रेणी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के तहत सूक्ष्म व छोटी सिंचाई योजनाओं के निर्माण से 1,724 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को सिंचाई क्षेत्र के अधीन लाया जा चुका है, जिससे 20, 795 परिवार लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि सिंचाई क्षेत्र में भी 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना क्षेत्र में फसल उत्पादन में 26 प्रतिशत की वृद्धि तथा सब्जी उत्पादन में 43 प्रतिशत वृद्धि हुई है जिससे ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिकी में भारी बदलाव आया है। इसके साथ-साथ पारम्परिक फसलों में भी 6 प्रतिशत तथा फल उत्पादन में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के तहत कार्यान्वित किए जा रहे वृहद पौधरोपण अभियान के कारण 8,119 हेक्टेयर क्षेत्र को वन क्षेत्र के अन्तर्गत लाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि भू-संरक्षण के लिए 3, 67, 681 ब्रश वुड चेक डैम, 71,944 पत्थरों के ढांचे और 62,074 तारों के ढांचे तैयार किए गए जिससे किसानों की उपजाऊ भूमि का संरक्षण सुनिश्चित हुआ है।

प्रो. धूमल ने कहा कि पेयजल सुविधाओं के सुधार तथा पेयजल समस्या से ग्रसित गांवों में 281नए जल स्रोत तैयार किए गए तथा 583 पुराने जल स्रोतों की मरम्मत की गई जिससे 45,700 परिवारों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि हरित क्षेत्र बढ़ाने से पशुपालन को प्रोत्साहन मिला है तथा गाय के दुग्ध उत्पादन में 11 प्रतिशत व भैंस के दुग्ध उत्पादन में 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

उन्होंने कहा कि यह परियोजना ग्रामीण आर्थिकी गतिविधियों को सुदृढ़ बनाने में वरदान साबित हो रही है तथा राज्य सरकार विश्व बैंक से आग्रह करेगी कि राज्य में और परियोजनाएं स्वीकृति की जाएं जिससे पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिलने के साथ-साथ लोगों की आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल सके।

टास्क टीम लीडर नॉरमन पिकार्नी ने परियोजना के अच्छे परिणाम हासिल होने पर मुख्यमंत्री को बधाई देते हुए कहा कि जल प्रबन्धन गतिविधियों को पूरे विश्व में और प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए ताकि सूख रहे पारम्परिक जल स्रोतों का जल स्तर बढ़ाया जा सके और गिरते भू-जल स्तर को रोका जा सके।

सहायक टास्क लीडर रंजन सामन्तरी ने कहा कि विश्व बैंक हिमाचल प्रदेश को कार्बन न्यूट्रल राज्य बनाने सम्बंधी जरूरतों पर ध्यान देगा।